रेगुलेटिंग एक्ट 1773 (Regulating Act of 1773)

gkgsnotes.com

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

- ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना (1600 ई.)
- निर्णायक युद्ध
  - प्लासी का युद्ध (1757)
  - बक्सर का युद्ध (1764)
- इलाहाबाद की संधि (1765): बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 'दीवानी' अधिकार प्राप्त
- द्वैध शासन (Dual Government): रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू (शक्ति बनाम जिम्मेदारी का अभाव)

एक्ट लाने के कारण (Reasons & Causes)

- कंपनी का वित्तीय संकट (Bankruptcy): 10 लाख पाउंड ऋण की मांग
- अधिकारियों का भ्रष्टाचार: 'नवाब' (Nabobs) संस्कृति और निजी व्यापार
- बंगाल का भीषण अकाल (1770): 1/3 आबादी की मृत्यु और कंपनी की संवेदनहीनता
- सैन्य विफलता: प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध में हैदर अली से हार
- वैश्विक कारक: चाय व्यापार में नुकसान और बोस्टन टी पार्टी
- लॉर्ड नॉर्थ की 'गुप्त समिति' (Secret Committee) की रिपोर्ट

प्रमुख प्रावधान (Main Features)

- केंद्रीयकरण की शुरुआत
  - बंगाल के गवर्नर को "गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल" बनाया गया
  - पहले गवर्नर जनरल: वारेन हेस्टिंग्स
  - मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया
- कार्यकारी परिषद (Executive Council) का गठन
  - 4 सदस्य: फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉन्सन और बारवेल
  - निर्णय बहुमत के आधार पर (गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं)
- न्यायिक व्यवस्था
  - 1774 में कलकत्ता (फोर्ट विलियम) में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
  - प्रथम मुख्य न्यायाधीश: सर एलिजा इम्पे
- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण: निजी व्यापार और उपहार/रिश्वत लेने पर पूर्ण प्रतिबंध
- संसदीय नियंत्रण: कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए सैन्य और राजस्व रिपोर्ट अनिवार्य

कमियां और खामियां (Drawbacks & Defects)

- गवर्नर जनरल की कमजोरी: परिषद के सदस्यों के साथ निरंतर टकराव
- न्यायिक अस्पष्टता: सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के कार्यक्षेत्र में टकराव
  - नंदकुमार का मुकदमा (1775): 'न्यायिक हत्या' (Judicial Murder)
- लूपहोल्स: 'आपातकाल' के नाम पर मद्रास और बॉम्बे की मनमानी (जैसे प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध)
- कानून का स्वरूप: भारतीयों पर अंग्रेजी कानून थोपना

संशोधन: एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781

- सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया गया
- गवर्नर जनरल और परिषद को न्यायिक जवाबदेही से छूट
- भारतीय धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों (Hindu/Muslim Laws) को मान्यता

महत्व (Significance)

- भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव
- कंपनी पर ब्रिटिश संसद का पहला सीधा नियंत्रण
- आधुनिक भारत का पहला लिखित कानून
- पश्चिमी न्यायिक प्रणाली का बीजारोपण

GKGSNOTES.COM

नोट: यह माइंड मैप केवल त्वरित रिवीजन (Quick Revision) के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस विषय को सभी कॉन्सेप्ट्स की विस्तार से समझने और संपूर्ण नोट्स पढ़ने के लिए कृपया gkgsnotes.com पर विजिट करें।

copyright © gkgsnotes.com | All Right Reserved